GENERAL STUDIES (Test–2)

Time allowed: Three Hours

DTVF/23 (J-A)–M–**GSM (P-III)-2302**

Maximum Marks:250

Name: Jatin Kumar

Mobile Number: ______________________________

Medium (English/Hindi): Hindi

Reg. Number: ________________________________

Center & Date: Online – 30.07.2023

UPSC Roll No. ***(If allotted)*:** ______________________

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*
All the questions are compulsory.
The number of marks carried by a question is indicated against it.
Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.
Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.
Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

(To be filled by Evaluator only)

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.	4	11.	7
2.	4	12.	7.5
3.	4.5	13.	6.5
4.	4	14.	7
5.	4	15.	6
6.	3.5	16.	2
7.	4.5	17.	1.5
8.	4	18.	7
9.	5	19.	6
10.	4	20.	5
Grand Total	41.5 + 55.5 =		97

Evaluator (Signature)

Reviewer (Signature)

Feedback

1. Context Proficiency
2. Introduction Proficiency
3. Content Proficiency
4. Language/Flow
5. Conclusion Proficiency
6. Presentation Proficiency

प्रिय छात्र,

- निमग्नता में आपका प्रश्नपत्र हल करने का तरीका शानदार है
  - data
  - facts
  - map
  - Proportionality

  का बखूबी प्रयास किया।

- एकाध प्रश्न में ज्ञान का अभाव था यथा-
  1 पैरा डिप्लोमेसी

- आप बहुत शानदार तरीके से पेपर को अप्रोच कर रहे हैं, इसे बनाये रखें।

You are doing well, keep it up.

Best wishes

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

GSMP (112) - 2302

UPSC

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

प्र० 1. "अध्यादेश का पुन: प्रख्यापन, संविधान के साथ एक छल तथा लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया का विध्वंश है।" प्रमाणित कीजिये।

उ० अध्यादेश से आशय राष्ट्रपति द्वारा (अनु. 123) अथवा राज्यपाल द्वारा (अनु. 213) प्रख्यापित ऐसे आदेश से है जो कानूनी रूप में किसी अधिनियम के समान होता है किन्तु संसद के किसी सदन के सत्र में नहीं होने अथवा दोनों सदनों के सत्र में ना होने पर प्रख्यापित किया जाता है।

अध्यादेश की प्रक्रिया -

1. राष्ट्रपति / राज्यपाल द्वारा अध्यादेश
2. 6 महीने एवं संसद के सदन में रखने पर 6 सप्ताह में पास किया जाना जरूरी अन्यथा समाप्त
3. कानून की तरह
4. पूर्व-समय से भी लागू किया जा सकता है
5. संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश नहीं
6. मंत्रिपरिषद द्वारा परामर्श के आधार पर ही सम्भव
7. बिना सदन के पटल पर अध्यादेश रखे, पुन: अध्यादेश जारी करना संविधान के खिलाफ

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए! Candidates must not write on this margin.

अध्यादेश का पुनः प्रख्यापन, संविधान के साथ छल तथा लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया का विध्वंश –

कार्यपालिका द्वारा विधायन जबकि यह विधायिका का कार्य है

Key Point

1. केवल अध्यादेश के आधार पर सरकार चलाने की कोशिश
2. केवल मंत्रिपरिषद की सहमति, सभी विधायकों अथवा सांसदों की सहमति नहीं
3. संविधान की मूल भावना के विरुद्ध
4. सदन में गहन चर्चा का अभाव
5. विस्तृत वर्णन एवं दोष का समाधान असंभव
6. संसदीय समितियों की अनदेखी
7. डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य में SC ने इसे संविधान के विरुद्ध माना

अतः अध्यादेश को प्रख्यापित करना केवल विशेष परिस्थितियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त खिड़की है जिसे उत्तरदायी तरीके से देश के विकास में उपयोग करना चाहिए।

4/10

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

(2) "मूल संरचना का सिद्धांत आवश्यक व वांछनीय दोनों है।" कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

'मूल संरचना' भारतीय संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है। इसका वर्णन मुख्यत: केशवानन्द भारती मामले, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय मूल संरचना के तत्वों को बढ़ाता रहा है। (यह है क्या यह बताओ)

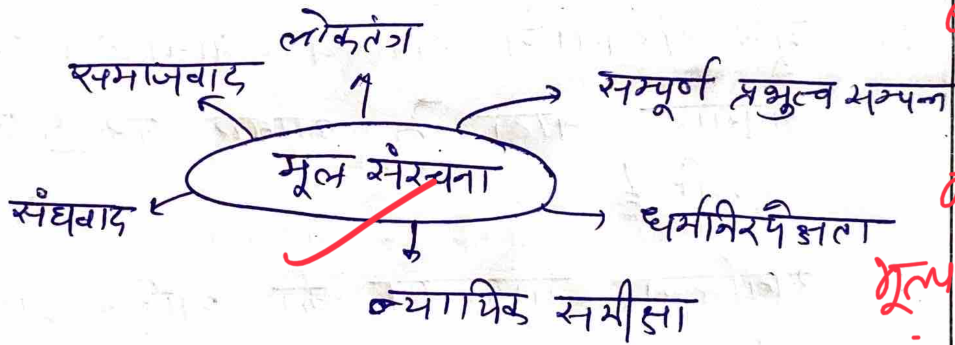

वह संवैधानिक मूल्य जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता

मूल संरचना का सिद्धांत आवश्यक क्यों?

1. ताकि कोई भी सरकार संविधान में आमूल-चूल एवं मनमाने परिवर्तन ना कर सके
उदा॰ - धर्मनिरपेक्षता समाप्त नहीं

2. संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए
उदा॰ - संविधान के मूल तत्वों की रक्षा

3. सरकार के सभी अंगों में कार्यों का स्पष्ट पृथक्करण बना रहे एवं अतिव्यापन नहीं हो
जैसे - NJAC को न्यायपालिका द्वारा गैरसंवैधानिक घोषित करना

मूल संरचना वांछनीय क्यों ?

1. मूल संरचना पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं है
2. मूल संरचना में सर्वोच्च न्यायालय अपने अनुसार वादों के आधार पर परिवर्तन करती है
3. सर्वोच्च न्यायालय की अधिक शक्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं।

अतः मूल संरचना हालांकि संविधान में वर्णित नहीं है किन्तु भारतीय संविधान के प्रत्येक तत्व का इससे प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः जुड़ाव है जिसे सरकार के तीनों अंगों द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए)

4/10

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

3 भारतीय प्रवासी समुदाय की प्रासंगिकता तथा भारत के आर्थिक व सामरिक हितों के संवर्धन में इनकी भूमिका पर चर्चा कीजिये।

प्रवासी समुदाय से आशय उन लोगों से है जो न्यूनतम 1 वर्ष एवं अधिकतम 7 वर्ष तक भारत की नागरिकता रखते हुए विदेशों में रहते हैं। ये लोग समय-समय पर भारत में आते रहते हैं।

भारतीय प्रवासी समुदाय की प्रासंगिकता:
- विश्व भर में भारतीय संस्कृति एवं इतिहास का प्रवास
- भारतीय विचारधारा का प्रवाह
- भारतीयता एवं वसुधैव कुटुम्बकम की धारणा
- विदेशी सम्बन्ध निर्धारण में अहम योगदान

भारत के आर्थिक हितों के संवर्धन में भूमिका

1. प्रवासियों द्वारा रेमिटेंस भेजना
   - भारत में सर्वाधिक $111.2 B
2. विदेशी निवेश को प्रोत्साहन
3. फोरेक्स रिजर्व में वृद्धि
4. विदेशी लोन एवं बहुपक्षीय संस्थानों से

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

लोन दिलाने में विश्वसनीय योगदान
जैसे - विश्व बैंक / IMF

सामरिक हितों के संवर्धन में भूमिका

1. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को प्रोत्साहन
   जैसे - भारत - UAE के हाल ही में बढ़ते सम्बन्ध
2. भारत की सॉफ्ट पॉवर के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में उपस्थिति
3. वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान एवं आपसी सम्बन्ध स्थापित करने में बेहतर समन्वय
   उदा॰ - भारत - अमेरिका सम्बन्ध
4. इंडोनेशिया, मलेशिया में प्रवासी भारतीय चीन की वन बेल्ट वन रोड नीति का विरोध

भारतीय डायस्पोरा विश्व के सभी कोनों में फैला हुआ है जिनके योगदान को देखते हुए भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है एवं PIO व OCI जैसे कार्डों पर भी जोर दिया जा रहा है।

Good

7.5/10

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

4. "राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक अनूठा मंच है, जिसे देश भर में पर्यावरणीय मुद्दों को स्वतः संज्ञान में लेने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।" इस संदर्भ में राष्ट्र के पर्यावरण शासन में NGT के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

उ०

NGT की स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधि॰ 1986 के तहत पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दों पर अपना निर्णय सुनाने के लिए किया गया था।

NGT का संघटन

- न्यायिक सदस्य
  - सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (अध्यक्ष)
  - \+ अन्य सदस्य
- गैर-न्यायिक सदस्य
  - सिविल समाज संगठन
  - प्रशासनिक अधिकारी
  - NGO आदि
- विशेष आमंत्रित सदस्य

NGT का कार्यक्षेत्र –

1. जल संरक्षण अधि॰
2. वायु संरक्षण अधि॰ 1981
3. पर्यावरण संरक्षण अधि॰ 1986
4. वन संरक्षण अधि॰ 1980
5. जल सेस अधि॰ 1977

पर्यावरण शासन में NGT का महत्व :-

1. सरकार के किसी कानून या नीति-निर्माण पर सरकार को परामर्श प्रदान करना
उदा० - नवीन वन (संशोधन) विधेयक

2. पर्यावरणीय मुद्दों का स्वत: संज्ञान लेना
जाँच का आदेश एवं निर्णय क्रियान्वयन प्रक्रिया

3. पर्यावरण को हानि पहुँचाने वाली योजनाओं पर रोक का आदेश

4. न्यायालयों पर कम बोझ एवं तीव्र निर्णयन प्रक्रिया जिससे समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके

5. पर्यावरण को होने वाली हानि अथवा लोगों की क्षति के पुनर्भरण का आदेश

NGT अपने कार्य में (पर्यावरण को बचाने) प्रभावकारी सिद्ध हुआ है किन्तु NGT को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने एवं इसके विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है।

Good

4/10

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

5. भारत में न्यायिक सक्रियता का महत्वपूर्ण योगदान एक सुरक्षा वाल्व तथा यह विश्वास प्रदान करना है कि न्याय पहुँच से परे नहीं है। कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

न्यायिक सक्रियता से आशय न्यायालयों द्वारा सरकार के किसी अंग द्वारा असंवेदनशीलता प्रकट करने अथवा जनोपयोगी कार्य पर ध्यान ना देने पर हस्तक्षेप करके न्याय सुनिश्चित करना है।

और (सहीक परिभाषा है) →
आपको कार्यक्षेत्र in वाद्द मा4 कर्ण।

न्यायिक सक्रियता का प्रभाव –

1. संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध किसी भी कानून अथवा नियम को गैर-संवैधानिक घोषित करना Basic structure
   जैसे - अनु. 13 में मूल अधिकारों के विरुद्ध होने पर ✓

2. समाज को न्याय की सुलभता
   जैसे - PIL की संकल्पना ✓

3. विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों में सकारात्मक हस्तक्षेप ✓

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

4. संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करना
5. जनता द्वारा तंत्र में विश्वास वृद्धि
6. सभी अंगों की जवाबदेहिता सुनिश्चित

न्यायिक सक्रियता से न्यायिक ओवररीच

1. न्यायालयों द्वारा सरकार के विधि निर्माण में अनावश्यक हस्तक्षेप
   उदा० – न्यायालय तृतीय सदन की भांति
2. शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का विरोध
3. न्यायालयों पर अनावश्यक बोझ
   उदा – 5 करोड़ केस पहले ही पेंडिंग
4. न्यायालय विधि एवं संविधान की व्याख्या में सक्षम जबकि हर प्रकार की कानून की व्याख्या में योग्यता संभव नहीं

अतः न्यायपालिका को अपने क्षेत्रीय परिधि में कार्य करते हुए लोगों की भलाई के लिए अग्रसर रहना चाहिए।

4/10

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

6 चुनावों के राज्य वित्तपोषण की अवधारणा से आप किस सीमा तक सहमत हैं।

उ० चुनावों की प्रक्रिया दिन-ब-दिन खर्चीली होती जा रही है। अतः एक नयी संकल्पना सामने आयी है - चुनावों के राज्य वित्तपोषण की संकल्पना। इसका अर्थ है कि चुनावी प्रक्रिया एवं भागीदारों को चुनावी खर्च सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाये।

चुनावी वित्तपोषण के लाभ -

1. सभी कैंडिडेटों को समान अवसर की प्राप्ति
2. चुनाव में अनावश्यक धन व्यय पर रोक
3. चुनाव के बाद होने वाले राजनीतिक-नौकरशाही गठजोड़ से भ्रष्टाचार की संभावना कम
4. शासक दल को अनुचित लाभ की संभावना कम

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए! Candidates must not write on this margin.

5. राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश

6. वंशवादी राजनीति पर रोक

चुनावी वित्तपोषण से हानियां -

1. सरकार/राज्य पर अनावश्यक बोझ
2. चुनावी खर्चों पर निगरानी में समस्या
3. स्वयं के धन का उपयोग फिर भी संभव
4. राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव
5. लोगों द्वारा धनार्जन का स्रोत बनाना
6. संसाधनों की बर्बादी

चुनावी वित्तपोषण की आवश्यकता अभी प्रतीत नहीं होती बल्कि हमें चुनाव आयोग को एक पूर्ण स्वायत्त संस्था बनाते हुए अधिक शक्ति सम्पन्न करने की आवश्यकता है ताकि राजनीतिक अपराधीकरण पर अंकुश लगाया जा सके।

विधि आयोग, ADR जैसे संगठनों को Quote करें

3.5/10

7. सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेहिता को लागू करने और प्रशासन में पारदर्शिता लाने का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। भारत में सामाजिक अंकेक्षण के लिये उपलब्ध विभिन्न विधायी समर्थनों पर प्रकाश डालिये।

उ० सामाजिक अंकेक्षण से तात्पर्य किसी योजना के क्रियान्वयन एवं उसके परिणाम पर लाभार्थी अथवा स्थानीय निकायों द्वारा अंकेक्षण करना है जैसे- मनरेगा। ✓

पारदर्शिता ← आशा / हित / जागरूकता

जवाबदेहिता को लागू करने मे
- → संसाधनों के बारे में पूर्ण जानकारी ✓
- → लाभार्थियों तक सीधी पहुँच ✓
- → कार्य की गुणवत्ता ✓
- → लाभार्थी की जगह योजना में भागीदार की तरह ✓

प्रक्रिया –

योजना का निर्धारण ✓ → डाटा एकत्र करना ✓ → डाटा को समन्वित करना ✓ → समिति का निर्माण ✓ → डाटा का ग्रामीण रूपांतरण ✓ → क्रियान्वयन एवं फीडबैक ✓

पारदर्शिता लाने में -

- लाभार्थी एवं कार्यक्रम के बारे में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध
- लोगों में जागरूकता - अधिकारों के प्रति
- बाह्य व आन्तरिक स्रोतों से जैसे - RTI आदि

उपलब्ध विधायी समर्थन :-

1. सूचना का अधिकार अधि० 2005 -
   - लोगों की लोक प्राधिकरणों में सूचनाओं तक पहुँच
2. सिटीजन चार्टर -
   - कार्यालयों द्वारा अपने द्वारा प्रदत्त सेवाओं का विवरण
3. स्थानीय कार्यों पर ग्राम सभा का नियंत्रण
4. विद्यालयों में स्थानीय लोगों की समितियां
5. डिजीटल रूप से सूचनाओं का सार्वजनिकीकरण
6. व्हिसल ब्लोअर अधि०

पारदर्शिता व जवाबदेहिता, सुशासन के महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनके आधार पर लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण स्थापित किया जा सकता है।

good

4.5/10

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

8. प्रस्तावित बहु राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 2022 भारत में सहकारी समितियों के संचालन में सुधार का उद्देश्य रखता है। इस संशोधन के महत्व पर बल देते हुए इसके प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिये।

बहु-राज्य सहकारी समितियां ऐसी सहकारी समितियां (अनु. भाग IX B) हैं जो एकाधिक राज्यों में अपना कार्य संचालन करती है जैसे अमूल आदि। Societies reg. act मेंशन करो

विधेयक में संशोधन का महत्व :-

1. पारदर्शिता - विधेयक सहकारी समितियों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। ✓

'Board'

2. विधेयक लोगों के प्रति जवाबदेहिता को बढ़ावा देगा। ✓

3. लोगों के मध्य लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की जागरूकता एवं प्रचार सम्भव हो सकेगा। ✓

4. समय पर चुनाव सम्पन्न किये जा सकेंगे एवं सभी की भागीदारी सुनिश्चित होगी। ✓

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए! Candidates must not write on this margin.

5. किसानों को (हितधारकों) ~~अपनी~~ उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा

6. प्रसंस्करण, संग्रहण, परिवहन पर अधिक जोर दिया जा सकेगा।

7. सरकार द्वारा निगरानी संभव होगी।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान।

Election
Board
Auditing

1. किसानों को अधिकतम लाभ मिले अर्थात् उनकी उपज के मूल्य की सुनिश्चितता

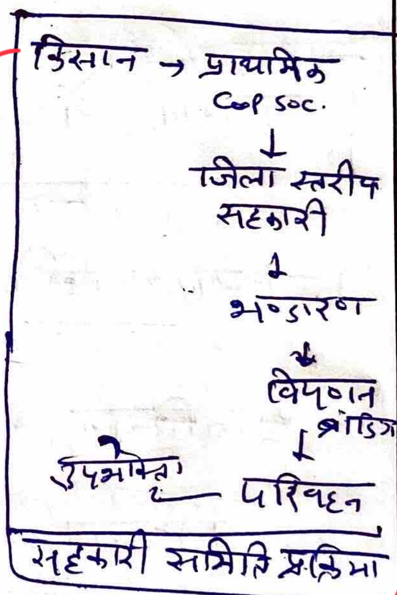

2. चुनाव प्रक्रिया समय से सम्पन्न करायी जाये।

3. प्रबंधन में महिला प्रबंधक / SC / ST की उपस्थिति अनिवार्य

4/10

सहकारी समितियां संवैधानिक है एवं व्यक्ति का मूल अधिकार है अतः राज्य को सुनिश्चितता हेतु आवश्यक निवेश एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि ये GDP में योगदान में वृद्धि कर सकें।

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

9. 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये, जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

73 वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिकता प्रदान की गयी। इन्हें संविधान के भाग - IX में अनु॰ 243 के तहत स्थान दिया गया।

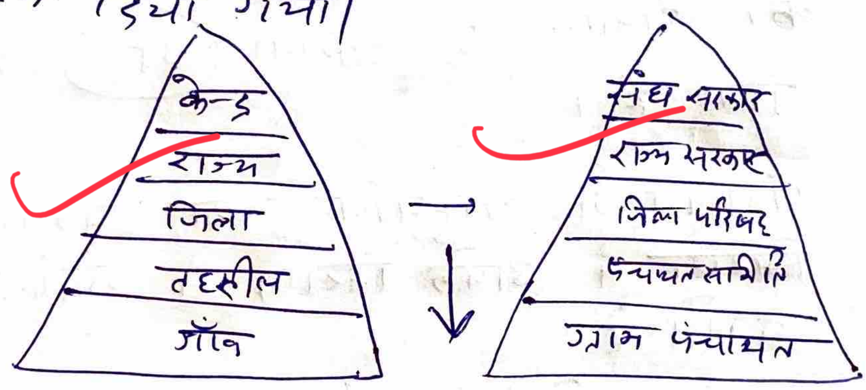

विकेन्द्रीकरण

जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना में भूमिका

1. ग्राम सभा का प्रभुत्व बढ़ा जिससे स्थानीय संसाधनों का संरक्षण एवं सदुपयोग संभव हुआ

2. धरातल पर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं निगरानी सुनिश्चित हुई

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

3. महिला सशक्तिकरण - 50% पदों पर महिलाएँ
उदा. डुफ्लो एवं राघवेन्द्र चौधरी के अनुसार जहाँ महिला सरपंच है वहाँ पेयजल पर अधिक खर्च होता है।

4. जनभागीदारी में वृद्धि - स्थानीय राजनीति

आलोचनात्मक मूल्यांकन

1. पंचायतों को कार्यों, धन एवं कार्मिकों का अभाव का सामना (3Fs) करना पड़ता है। good

2. पंचायत में बाहुबलियों का प्रभाव जिससे वे अपने हिसाब से नीतियां बनाते हैं।

3. सरपंच पति / पिता / पुत्र की प्रथा

4. लोगों में जागरूकता का अभाव

5. चुनावी कार्यों के दौरान धन एवं बल का प्रयोग

पंचायती संस्थाओं ने लोकतंत्र को तृणमूल स्तर पर स्थापित किया है किन्तु कुछ समस्याएं हैं जिन्हें सामाजिक संगठनों, मीडिया व जनभागीदारी से दूर किया जा सकता है।

5/10

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

10. जनगणना में होने वाली देरी से विकासात्मक पहलों की प्रभावशीलता और दक्षता प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। चर्चा कीजिये।

भारत में अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। प्रति 10 वर्ष पर जनगणना कराने पर 2021 की जनगणना अभी नहीं हुई है जिसका एक कारण COVID-19 है। जनगणना को जनगणना अधि. 1948 के तहत कराया जाता है।

जनगणना के प्रश्न →
- नाम
- पिता / पत्नी का नाम
- निवास
- शिक्षा का स्तर
- रोजगार
- आमदनी

जनगणना में देरी का प्रभाव -

1. खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने में समस्या - 2011 की जनगणना के अनुसार 81 करोड़ जनसंख्या NFSA के दायरे में किन्तु 2021 तक जनसंख्या बढ़ी अतः उन लोगों पर ध्यान नहीं

उदा० - हिमाद्री अलारिया बनाम राजस्थान राज्य केस

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

2. ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने में विफलता

3. नीति निर्माण पूर्व जनसंख्या के आधार पर – क्रियान्वयन मे समस्या

4. IMR, MMR, TFR पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं

5. जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण प्रक्रिया में कमी

6. क्षेत्र आधारित एवं वर्ग आधारित विकास योजनाओं की प्रभावशीलता में कमी → डाटा का अभाव

7. अपराधों को रोकने, उनके बढ़ने की दर, आवश्यक संसाधन आदि पर नियंत्रण नहीं

अतः समयबद्ध जनगणना समय की माँग है जिससे प्रत्येक लाभार्थी के लिए योजना निर्माण सम्भव हो सके एवं गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का निपटारा हो सके।

4/10

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

(11) बदलते भू- राजनीतिक परिदृश्य के आलोक में भारत-जापान सामरिक संबंधों में सहयोग के उभरते क्षेत्र और चुनौतियाँ क्या हैं।

प्राकृतिक मित्र
अपरिहार्य सहयोगी > ऐसे शब्द प्रयुक्त करें

जापान, चीन के पूर्वी भाग में स्थित एक विकासित देश है। भारत-जापान एशियाई शक्तियाँ है।

भारत-जापान सामरिक संबंधों में सहयोग :

1. सैन्य अभ्यास -
   - JIMEX - मिलिट्री अभ्यास
   - मालाबार - भारत - अमेरिका - जापान - आस्ट्रेलिया का अभ्यास

2. व्यापारिक मामलों में हिस्सेदारी - free trade agreement
   - जापानी ऑटोमोबाइल कम्पनी एवं मोबाइल कम्पनी भारत में

3. जापानी प्रमुखों की भारत यात्रा -
   - शिंजो एबे ने भारत को सदाबहार दोस्त कहा (twin city) बनारस -

4. समान समुद्री हित -
   - चीन के विरुद्ध

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

उभरते क्षेत्र — Investment < Bullet train, DMIC

1. **आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस** -

   - जापान तकनीकी रूप से उन्नत अत: AI मे सहयोग संभव

2. **अंतरिक्ष सहयोग** -

   - JAXA व ISRO के मध्य सहयोग

3. **विज्ञान व प्रौद्योगिकी** -

   - आपसी हितों को ध्यान में रखकर विज्ञान व प्रौद्योगिकी का लोगों की भलाई मे उपयोग

4. **QUAD** -

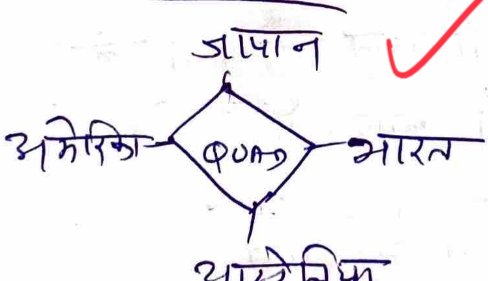

एक अनौपचारिक संघटन जिसे सैन्य संगठन माना जा रहा है.

5. सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन

6. सांस्कृतिक आदान-प्रदान

(7) N.E. में Investment
(8) Asia-Africa growth corridor

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

चुनौतियाँ - Project emplimentation में देरी

1. चीन का बढ़ता प्रभुत्व -
   - द० चीन सागर में प्रवेश
   - भारत की सम्प्रभुता का अहित
   - चीन की वन बेल्ट वन रोड नीति
2. UN जैसी संस्थाओं की उदासीनता -
   - परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध
3. जापान एकमात्र देश है जिसने परमाणु हमलों को झेला है
4. जापान का रूस के साथ कुरिल द्वीप को लेकर विवाद
5. क्षेत्रीय समूह में (BRICS, SAARC) जापान व भारत की अनुपस्थिति

जापान - भारत के सम्बन्ध धीरे-धीरे गति पकड़ रहे हैं। हमें QUAD का सहारा लेकर जापान के साथ सम्बन्धों को अधिक गति देने की आवश्यकता है ताकि भारत दक्षिण का सशक्त नेतृत्वकर्ता बन सके।

Good

7/15

Page

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

12 समकालीन वैश्विक व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र के महत्व का आकलन कीजिए तथा इसके सुधार और पुनरुद्धार की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये।

संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापना 1945 में विश्व युद्ध (II) की समाप्ति के बाद किया गया था।

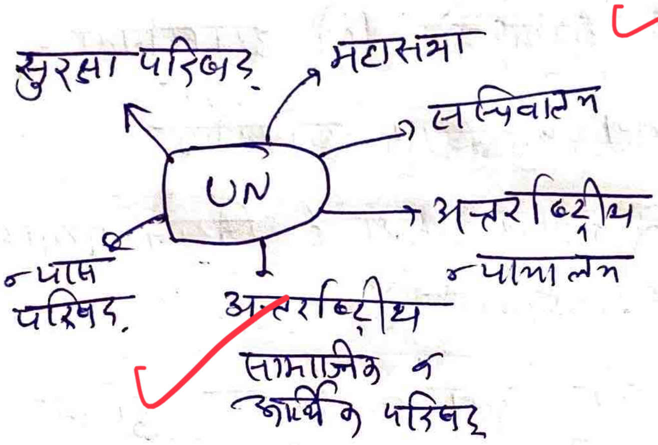

UN के अंग

UN के कार्य → वैश्विक शांति व सुरक्षा को स्थापित करना

- साम्राज्यवाद को फैलने से रोकना
- जलवायु परिवर्तन व आतंकवाद पर चर्चा
- नवीन उभरते वैश्विक खतरों पर विश्व का ध्यान आकर्षित करना
- विभिन्न देशों के मध्य विवादों का समाधान करना

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

संयुक्त राष्ट्र का महत्व :-

1. अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का स्थायी समाधान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है जैसे - भारत-पाकिस्तान का कुलभूषण जाधव केस।

2. साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए एवं नव-उपनिवेशवाद की रोकथाम
जैसे - चीन का दक्षिणी चीन सागर में बढ़ता प्रभुत्व

3. वैश्विक परिदृश्य में गरीब देशों पर विभिन्न खतरों का आकलन एवं आगामी संकटों के प्रति चेतावनी
जैसे - जलवायु परिवर्तन

संयुक्त राष्ट्र में सुधार एवं पुनरुद्धार की आवश्यकता :-

1. अत्यधिक पुरानी संस्था -
 - 1945 में स्थापित
 - लगभग 75 साल पुरानी

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

2. वैश्विक भू-राजनीति मे परिवर्तन -
- विश्व बहुध्रुवीकरण की ओर
- USSR का पतन
- चीन व भारत का बढ़ता प्रभाव

3. अहम मुद्दों पर निर्णय नहीं
जैसे - भारत-पाकिस्तान के मध्य
जम्मू-कश्मीर मुद्दा।

russia ukraine war

4. चीन जैसे देशो द्वारा निर्णय अस्वीकार करना - अतः निर्णय क्रियान्वयन के लिए उचित प्रशासनिक ढाँचे की आवश्यकता

5. सुरक्षा परिषद् मे सुधार - वीटो पावर

संयुक्त राष्ट्र, तृतीय विश्व युद्ध की संभावना को रोकने में सफल हुआ है किन्तु एक पुरातन संस्था के रूप में, इसके स्थायीत्व पर प्रश्नचिह्न है। इसमें नवीन परिवर्तनों एवं सुरक्षा परिषद् मे नये देशों को लाये जाने पर विचार की आवश्यकता है।

7.5/15

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

13 उन कारकों एवं भू- राजनीतिक हितों पर चर्चा कीजिये जो मध्य एशिया के साथ भारत के संबंधों को एक आकार प्रदान करते हैं। उन कदमों का भी उल्लेख कीजिये जिन्हें भारत को इस क्षेत्र में अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए उठाने की आवश्यकता है।

मध्य एशिया एवं भारत के सम्बधों में स्थलीय भाग का अधिक महत्व है क्योंकि मध्य एशीया के अधिकांश देश, स्थलबद्ध हैं।

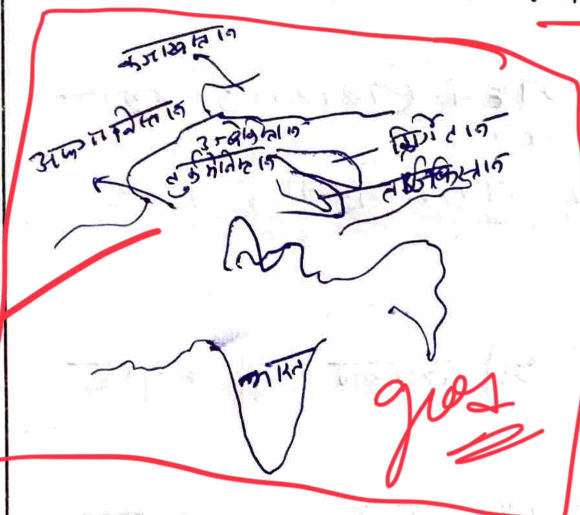

भू-राजनीतिक हित –

1. एक शांत, स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी एवं समावेशी एशिया की संकल्पना
2. मध्य एशिया में तेल व प्राकृतिक गैस के भण्डार
3. स्थल मार्ग से निकटता
4. ऐतिहासिक कारक - मुगल मध्य एशिया से ही भारत आये थे

5. दक्षिण - दक्षिण सहयोग —
- विकसित व विकासशील देशों के मध्य आपसी अन्तर्द्वन्द्व
- दक्षिण - दक्षिण सहयोग आवश्यक
- भारत का बढ़ता प्रभाव

6. SCO में सभी मध्य एशियाई देश (अफगानिस्तान व तुर्कमेनिस्तान) के अतिरिक्त

7. मुस्लिम देशों में भी भारत की स्पष्ट आवाज
उदा. - अल्पसंख्यक व मुस्लिमों पर अत्याचार करने के विपक्ष में भारत की आवाज

समस्याएँ —

1. चीन का स्पष्ट प्रभाव —
- वन बेल्ट वन रोड नीति
- पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह

2. अफगानिस्तान में तालिबान का शासन

3. पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद

4. अस्थिर सरकारें
5. तकनीकी व निवेश का अभाव

पहुँच बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम

1. SCO के मंच का अधिकाधिक उपयोग किया जाये
2. लुक नॉर्थ की नीति
3. पंचशील सिद्धान्त - शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व एवं अनाक्रमण
4. तालिबान सरकार से भी राष्ट्रीय हित में संबंध बढ़ाने पर प्रयास किया जाना चाहिए
5. चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए मध्य एशीया में निवेश व तकनीकी सहयोग। विश्वविद्यालय, अनुसंधान के स्तर पर लोगों के मध्य सहयोग।

अतः मध्य एशीया भारत के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है भले वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिती दर्ज कराने मे हो या दक्षिण का नेतृत्वकर्ता बनने में।

6.5/15

15 संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एक समान नागरिक संहिता की 'आशा' और अपेक्षा की थी, लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस संदर्भ में भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है।

समान नागरिक संहिता (अनु० 44), DPSP में वर्णित है जिसका आशय है कि सभी धर्मों के नागरिक कानूनों में समानता अर्थात विवाह, तलाक, हस्तांतरण व गोद लेना आदि।

UCC की आवश्यकता क्यों –

1. विविध धर्मों में एकता लाने जिससे भारत की एकता व अखण्डता अक्षुण्ण की जा सके।

2. सभी महिलाओं को समानता का अधिकार मूल रूप में दिया जा सके।

उदा० – तीन तलाक में महिलाओं को कम अधिकार

– शायरा बानो केस में – तीन तलाक अवैध घोषित

3. UCC से न्यायालय में नागरिक केसों की संख्या कम होगी।
Eg. एक ही निर्णय सभी धर्म के लोगों पर लागू होगा।

4. धर्म की मनमानी व्याख्या पर रोक लगेगी जिससे सभी को समान अधिकार मिलेंगे।

5. धर्म की राजनीति पर रोक लगेगी
उदा० - चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता में रोक

चुनौतियां

जनजातीय विविधता
→ North eastern region Specially

1. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार -
अनु० 25, 26, 27, 28 - धर्म को अबाध रूप से मानने आचरण करने, प्रबन्ध करने की स्वतंत्रता का विरोध।

Good

2. धार्मिक समुदायों द्वारा विरोध सम्भव
3. निजता के अधि० (अनु - 21) - के० एस० पुट्टास्वामी केस - का विरोध
4. भारत की विविधता पर संकट
उदा० - सभी धर्म एक हो जाएंगे

(Please do not write anything except the question number is this space) कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए! Candidates must not write on this margin.

5. UCC, DPSP का हिस्सा है अतः आवश्यक नहीं किन्तु राज्य को प्रयास करना चाहिए।

6. विवाह, तलाक, हस्तांतरण जैसे कानूनों में परिवर्तन की अत्याधिक वृहत् प्रक्रिया

संभावित कदम -

1. UCC को क्रमानुगत तरीके से लागू करना चाहिए। पहले सभी समुदायों के मध्य विश्वास स्थापित करने की आवश्यकता।
2. धार्मिक गुरुओं, मौलवी, महन्तों आदि द्वारा सहयोग लिया जाये।
3. गोवा मॉडल से सीख ली जा सकती है।
4. सभी हितधारकों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता।

विधि आयोग के अनुसार -
UCC ना तो आवश्यक है और ना ही जरूरत। अतः सभी धार्मिक समुदायों के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाने की आवश्यकता है।

good

7/15

(15) "भारतीय संसद एक संप्रभु विधायिका नहीं है; इसकी शक्तियाँ विशाल है लेकिन असीमित नहीं।" कथन पर टिप्पणी कीजिये।

भारतीय संसद, विधि निर्माण का कार्य करती है जिसमें दो सदन है - लोकसभा व राज्यसभा।

विधि निर्माण प्रक्रिया -
↓
लोकसभा/राज्यसभा → राज्यसभा/लोकसभा
↓
राष्ट्रपति

संसद को प्राप्त शक्तियाँ -

1. संसद देश के संचालन के लिए विधियों का निर्माण करती है।
2. सार्वजनिक मुद्दों पर बहस, वाद-विवाद एवं निर्णयन प्रक्रिया
   जैसे - CAA व NRC
3. राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
4. सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायधीश/राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति को पद से हटाना

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

(5) बजट पास करना एवं विधि पर नियंत्रण।

संसद की शक्तियों की परास : good points

1. संसद राष्ट्रीय महत्त्व के किसी मुद्दे पर कानून बना सकती है। जैसे - पर्यावरण संरक्षण अधि॰ 1986

2. संसद, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।
— जब राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे।

3. संसद, सरकार की जवाबदेहिता को स्थापित करती है।
उदा॰ - वाद-विवाद, डिबेट, संसदीय समितियों की रिपोर्ट पर चर्चा

4. संसद संविधान में संशोधन कर सकती है
उदा॰ - GST - 101वाँ संविधान संशोधन

5. संसद, किसी कार्यपालक को समन कर सकती है एवं उससे कार्य के प्रति जवाब मांग सकती है।

6. संसद व्यक्ति के मूल कर्तव्यों के निर्धारण के लिए कानून बना सकती है।
उदा॰ - राष्ट्रीय ध्वज अपमान निरोधक अधि॰ 1971

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

संसद की शक्तियां असीमित नहीं -

(1) मूल अधिकार - संसद द्वारा निर्मित विधियां व्यक्ति के मूल अधिकार पर अतिक्रमण ना करती हैं। अन्यथा उन्हें शून्य घोषित किया जा सकता है।
→ अनु॰ 13 के तहत

(2) मूल संरचना - संसद, मूल संरचना (समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र आदि) के विरुद्ध विधि निर्माण नहीं कर सकती।
उदा॰ - केशवानन्द भारती केस, 1973

(3) संविधान में उल्लेखित नहीं होने पर किसी विषय पर संसद विधि नहीं बना सकती। इसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक है।

verify it

→ अवशिष्ट शक्तियां → संघ सरकार

(4) न्यायिक समीक्षा

अत: ~~यह~~ स्पष्ट कहा जा सकता है कि संसद की शक्तियां अत्याधिक विशाल है ~~किन्तु~~ वे अन्तत: लोगों/संविधान व न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह हैं। इससे नागरिक केन्द्रित संसदीय व्यवस्था ~~की~~ स्थापना होती है।

6/16

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

16 वैश्वीकरण के युग में, विदेश नीति को आकार देने में पैरा डिप्लोमेसी की अवधारणा का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ा है। और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अराष्ट्रीय अभिकर्ताओं की बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित करता है। भारत के संदर्भ में सविस्तार वर्णन कीजिए।

पैरा-डिप्लोमेसी से आशय उन क्षेत्रों में भी कूटनीतिक प्रक्रिया अपनाने से है जिनमें अभी तक इनने कोई कार्य नहीं किया है।

स्थानीय निकायों, राज्य सरकारों की भूमिका

इसकी परिभाषा लिखें

पैरा डिप्लोमेसी का बढ़ता महत्व :-

1. वैश्विक परिदृश्य का बदलता स्वरूप
2. चीन का उत्तरोत्तर बढ़ता प्रभाव
3. पाकिस्तान की विरोधी गतिविधियां एवं आतंकवाद को प्रोत्साहन
4. भारत की बढ़ती जनसांख्यिकी
5. भारत का untapped क्षेत्र जहाँ विकास की सम्भावनाएं हैं
6. समुद्री संसाधनों में उपयोग

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

भारत के संदर्भ मे पैरा डिप्लोमेसी -

1. भारत एक जनांकिकी लाभांश वाला देश है जिसकी औसत आयु 28 है अतः विकास की सभी संभावनाएँ खुल रही है।

2. भारत के पास कोयला लोहा के अत्यधिक संसाधन मौजूद है और तकनीकी व निवेश की अनुपलब्धता के कारण अत्यधिक कम उपयोग किए गये है।

3. भारत का विशाल EEZ क्षेत्र जिसके संसाधनो के साथ - साथ भारत का रणनीतिक हित भी है।

अतः पैरा डिप्लोमेसी भारत के विकास एवं भविष्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है। सभी भागीदारो को साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

2/15

17 भारत की राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति के उद्देश्य, लक्ष्यों और महत्व पर चर्चा कीजिये।

भारत की राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति भारत को महत्वपूर्ण भू-स्थानिक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने पर फोकस करती है।

फोकस मुख्य → विश्व के महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता
→ भारत एक प्रमुख निर्यातक के रूप में
- निजी क्षेत्रों का प्रवेश
- निवेश की आवश्यकता
- लोगों की निजता की सुरक्षा

महत्व – भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश
- दक्षिण की उभरती हुई शक्ति
- चीन को काउंटर करने में
- UNSC में सदस्यता स्थायी

अतः राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति भारत को विश्व पटल पर अहम देश बनाने में योगदान देगी।

1.5/15

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

19 "गरिमा मानव जीवन का सार है। और यही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का लक्ष्य है। मानवाधिकारों के संरक्षण में NHRC के प्रदर्शन का मूल्यांकन कीजिये।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना राष्ट्रीय मानवाधिकार अधि॰ के तहत 1992 में की गयी। इसका मूल उद्देश्य व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा एवं व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने से है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ढांचा -

1. अध्यक्ष (S.C का पूर्व न्यायाधीश)
 + सदस्य (महिला / SC / ST / OBC / सफाई कर्मचारी व बाल आयोग के अध्यक्ष)
2. अधिकतम आयु 3 वर्ष / 70 वर्ष आयु
3. सरकार द्वारा नियुक्ति
4. विधिक संरक्षण प्राप्त

NHRC के कार्य -

1. व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा करना

2. जेलों का निरीक्षण एवं कैदियों की स्थिति जानने का प्रयास करना

3. किसी स्थान पर मानवाधिकार हनन का suo-moto संज्ञान लेना

4. सरकार को मानवाधिकार से सम्बन्धित कानून निर्माण में परामर्श देना

5. अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार शर्तों, समझौतों आदि को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करवाना

6. विधि क्रियान्वयन पर निगरानी करना

समस्याएँ →
- परामर्श बाध्यकारी नहीं
- स्वयं की जाँच विंग नहीं
- अध्यक्ष व सदस्यों के पास अल्प समय
- सदन में NHRC की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं होना
- आदेशों के क्रियान्वयन के लिए ढाँचा नहीं

प्रदर्शन का मूल्यांकन :-

1. रिपोर्ट बनाने में देरी
2. मणिपुर हिंसा का संज्ञान नहीं लेना
3. जेलों की स्थिति में सुधार हेतु प्रयास

3. खुली जेल का सुझाव

4. राज्य मानवाधिकार आयोगों से परामर्श

5. एक वर्ष से अधिक पुरानी समस्याओं को सुनने का अधिकार नहीं

6. अत्यधिक समय लगना

समाधान :-

1. NHRC को स्वायत्तता दी जाये
जाँच विंग + कार्यकारी विंग

2. NHRC में कार्मिकों की संख्या में वृद्धि

3. NHRC के अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल में वृद्धि

4. 1 वर्ष तक के केस सुनने जैसे बिन्दुओं को हटा दिया जाये

5. NHRC में समयानुरूप नियुक्ति हो एवं इसकी रिपोर्ट सदन में चर्चा हेतु रखी जाए।

NHRC ने अपनी स्थापना से अब तक अनेक कार्यों में योगदान दिया है। इसे स्वायत्तता देने की आवश्यकता है ताकि यह पूर्णरूपेण अपना कार्य कर सके।

7/15

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

(19) स्वयं सहायता समूह देश के सामाजिक - आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा कीजिए।

स्वयं सहायता समूहों से आशय ऐसे समूहों से है जो लोगों द्वारा आपस में मिल-जुलकर बनाये जाते हैं इनका उद्देश्य आपसी सहायता करना होता है।

[illegible] → उपलब्धि, कुडुम्बश्री (केरल)

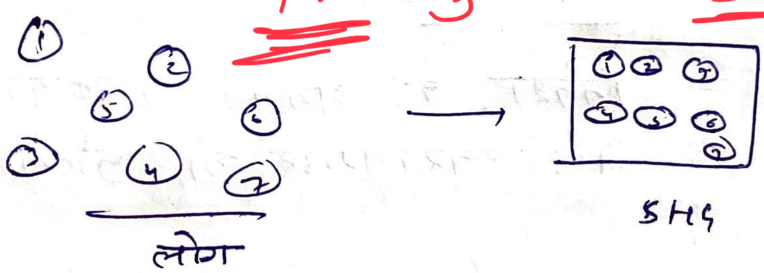

- यह एक अनौपचारिक संगठन है और आपसी विश्वास पर कार्य करता है।

SHG देश के आर्थिक -सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण -

1. SHG को निवेश की प्राप्ति जिससे कुटीर व लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके।

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

2. महिला सशक्तिकरण - महिलाएं आगे आकर SHG का निर्माण करती हैं एवं भागीदारी का प्रोत्साहन करती है।

3. पितृसत्तात्मकता के विरुद्ध -
- स्वयं आत्मनिर्भरता
- महिलाओं में सोच का विकास एवं स्वतंत्रता

4. रोजगार में वृद्धि -
- निवेश व धन की उपलब्धता अतः स्वरोजगार को प्रोत्साहन

समस्याएं - महिलाओं पर सामाजिक दबाव
- पितृसत्तात्मक सोच
- महिलाओं के प्रति समाज का नकारात्मक नजरिया
- बैंकों द्वारा लोन देने में आनाकानी

समाधान - SHG को विधिक संरचना देने एवं अधिकार स्वरूप स्थापित करना
- SHG में महिलाओं को बीमा
- ब्याज पर सबवेंशन स्कीम

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC
Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

[सरकार द्वारा उठाये गये कदम]

① संगठन से समृद्धि स्कीम -
- आपसी संगठन जिससे प्रतिवर्ष 1 लाख आल का लक्ष्य

SHG- Bank linkage

② SFURTI योजना
③ स्टार्ट अप योजना
④ स्टैण्ड अप योजना

अतः SHG भारत में एक क्रांतिकारी कदम है किन्तु सामाजिक स्तर पर परिवर्तन करके एवं विधिक स्थायीत्व एवं सुरक्षा द्वारा SHG में परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि इसे और अधिक सशक्त तरीके से स्थापित किया जा सके।

6/15

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

२० विश्व के लिये ताइवान के सामरिक महत्व का आकलन करते हुए यह निर्धारित कीजिये कि एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में इसकी अवस्थिति और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक सम्भावित फ्लैशपॉइंट क्षेत्र के रूप में यह 21वीं सदी में शक्ति के भू-राजनीतिक संतुलन को कैसे प्रभावित करता है।

ताइवान, चीन के दक्षिणी पूर्व में स्थित एक देश है ~~जिस पर~~ चीन अपना अधिकार समझता है किन्तु ताइवान स्वयं को एक भिन्न और स्वतंत्र देश मानता है।

ताइवान का सामरिक महत्व :-

1. चीन को प्रति-संतुलित करने में
2. एशिया व अमेरिका के मध्य संतुलन स्थापित करने में
3. दक्षिण व उत्तर के देशों के मध्य सम्पर्क बिन्दु के तौर पर
4. प्रशान्त महासागर में रणनीतिक व सामरिक स्थिति पर स्थित
5. ताइवान का चीन के साथ मतभेद

तकनीकी विकास → chip industry

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC
Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

भू-राजनीतिक संतुलन पर प्रभाव:-

(1) अमेरिकी उच्चाधिकारियों की ताइवान यात्रा → चीन द्वारा विरोध

(2) ताइवान → अर्द्धचालकों का महत्वपूर्ण निर्माता एवं निर्यातक

(3) ताइवान को UN में सदस्य एवं देश के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता

(4) भारत - ताइवान सम्बन्ध - अर्द्धचालक
↓
फॉक्सकॉन द्वारा हाल में वेदांता से सौदे के हाथ खींचना

अतः ताइवान पश्चिमी प्रशान्त महासागर का अति महत्वपूर्ण देश है जो वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर सकता है।

5/15